[Shri Jawaharlal Nehru]

are living there, which has resulted in this kind of thing.

**12.17 hrs**

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTEENTH REPORT

**Shri Krishnamoorthy Rao** (Shimoga): I beg to present the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

---

## STATEMENT BY A MEMBER AND MINISTER

**Shri Surendranath Dwivedy** (Kendrapara): Sir, you would remember that the other day when the Home Minister made some baseless charges against our Party, and when we challenged him, he promised to see me and give me such particulars as he had with him. You then observed that you would take a decision in the matter after hearing from us. Immediately on that very day, I wrote to the Home Minister asking him whether I could meet him in the course of the day or the day following. I received a letter from him saying that since yesterday was a holiday, he would look into the papers today and would meet me tomorrow.

This is a matter of great concern. As you know, we feel and think that the privilege of the House requires that either the charges should be withdrawn or the documents that he has in proof of the allegations should be laid on the Table of the House. I hope that when we meet we would probably be able to deal with that. We would then seek your guidance in the matter. But there has been some delay on account of a holiday coming in between.

**Shri Tyagi** (Dehra Dun): That is enough.

**Mr. Speaker:** I do not know if the hon. Home Minister would like to say anything.

**The Minister of Home Affairs (Shri Lal Bahadur Shastri):** I have nothing to add. I got his letter—it may have been sent on the 1st—yesterday and immediately I wrote to Shri Dwivedy that as the office was closed, I would look into the papers today and would meet him tomorrow and tell him whatever facts are with me.

**Mr. Speaker:** This is a matter on which Members are feeling very much exercised. Therefore, it is desirable that it should be done as early as possible.

---

**12.19 hrs.**

## DEMANDS FOR GRANTS*—*contd.*

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND REHABILITATION—*contd.*

**Mr. Speaker:** The House will now proceed with further discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation, together with the cut motions moved.

Shri Mohan Swarup may continue his speech.

**श्री मोहन स्वरूप** (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं परसों यह अर्ज कर रहा था कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त होना चाहिए क्योंकि यह भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार है । मैंने अर्ज किया था कि कांस्ट्रक्शन सोसाइटीज बननी चाहिएं और उनके द्वारा काम होना चाहिए । इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पी० डबल्यू० डी० में आइटम रेटस और परसेंटेज रेट्स का तरीका है उसको समाप्त किया जाए और लम्प सम काम देने की प्रणाली को अपनाया जाए । मेरे सामने

*Moved with the recommendation of the President.

पबलिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है । उस में भी इस चीज की सिफारिश की गयी है कि आइटम रेट्स पर काम न दिया जाए क्योंकि इस से करप्शन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ।

इसी के साथ में यह अर्ज करना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० में इस तरह की संस्था बने जोकि माडल प्लान्स तैयार करे और उनके एस्टीमेट भी बनाए और उन्हीं आधारों पर छोटी और बड़ी इमारतें बनायी जाएं । जैसे जैसे रेट्स घटे या बढ़े वैसे उन माडल्स के रेट्स में भी अन्तर कर दिया जाए ।

मैं चाहता हूं कि जब तक कि साइट का सिलेक्शन न हो जाए, और डिजाइन तैयार न हो जाए और जब तक साइट पर मैटीरियल न पहुंच जाए उस वक्त तक काम शुरू न हो ।

मरम्मत के लिए भी पी० डब्ल्यू० डी० में एक अलग से विभाग होना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है । इसको निगलेक्ट किया जाता है । तो उस पर बल दिया जाए ।

इसी के साथ में यह चाहता हूं कि स्टेंडरडाइजेशन आफ टैकनिकल रिक्वायरमेंट्स का भी विभागीकरण हो और रेट्स स्ट्रक्चर भी तैयार किया जाए और यह भी देखा जाए कि कितना मारजिन होता है ।

इसी के साथ साथ टैकनिकल आडिट की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है । जिस तरह आडिटर जनरल और कंट्रोलर जनरल है, उसी तरह पी० डब्ल्यू० डी० में एक अलग से टैकनिकल आडिट की व्यवस्था हो और वह पी० डब्ल्यू० डी० के असर से भी बाहर हो ।

इन चीजों के साथ साथ में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० में जो करप्शन है और जो काम में खराबियां हैं और जो कि रोजाना अखबारों में छपती हैं, उनकी तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए । अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यह करप्शन और बढ़ेगा और इस के लिए न केवल कैबिनेट जिम्मेवार होगी बल्कि पार्लियामेंट भी जिम्मेवार होगी कि क्यों इस करप्शन को जारी रखने दिया जाता है । मेरे पास इंजिनियर्स सिम्पोजियम की रिपोर्ट है, जो कि सन् १९६१ में हुआ था । उस में भी इस पर जोर दिया गया है । उस में कहा गया है :

"There was complete unanimity of opinion regarding the necessity for radical changes in the Public Works Department."

अन्त में मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं कि करप्शन को रोकने की तरफ ज्यादा ध्यान दें । इस डिपार्टमेंट का रिआरिएंटेशन होना चाहिए ।

अब मैं हाउसिंग की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं .....

**अध्यक्ष महोदय** : अब समाप्ति के बाद भी आप तवज्जह दिलाना चाहते हैं ।

**श्री मोहन स्वरूप** : अब मैं हाउसिंग के बारे में अर्ज करूंगा । मैं ने पबलिक वर्क्स के बारे में समाप्त किया है ।

हाउसिंग के बारे में दिल्ली और दूसरे शहरों के बारे में कहा गया, लेकिन रूरल हाउसिंग के बारे में नहीं कहा गया । यह बहुत बड़ी समस्या है । हमारे देश में ५,५८,१०० गांव हैं और उन में ५४ मिलियन मकान हैं जिन में गांवों की जनता रहती है और इन ५४ मिलियन घरों में से ५० मिलियन घर ऐसे हैं जिनको फिर से बनाया जाए या उन की मरम्मत की जाए । दुःख की बात है कि इतनी बड़ी समस्या को हल करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं किया गया । पहली प्लान में कुछ नहीं किया गया, दूसरी प्लान में इस के लिए १० करोड़ रुपया रखा गया और जब प्लान का रिएप्रेजल हुआ तो पांच करोड़ और बढ़ाया गया । इस

[श्री मोहन स्वरूप]

तरह १५ करोड़ की व्यवस्था की गयी । जो पांचवीं हाउसिंग मिनिस्टर्स कानफरेंस हुई उस में इस बात पर जोर दिया गया कि ३० करोड़ की व्यवस्था इस के लिए होनी चाहिए । जो कि नहीं की जा रही है ।

सन् १९५७ में विलेज प्रोजेक्ट हाउसिंग स्कीम बनायी गयी और उसके तहत कहा गया कि ६६⅔ पर सेंट की उनको सहायता मिलेगी या दो हजार रुपया दिया जाएगा जो भी कम हो । मेरी समझ में नहीं आता कि दो हजार या १ हजार रूपए से हाउसिंग की समस्या का कैसे समाधान हो सकता है ।

यह भी बताया गया कि गांव वाले रुपया नहीं लेना चाहते । मेरे खयाल में गांव के लोग यह समझते हैं कि दो हजार या एक हजार रुपए से कुछ होगा नहीं कर्जा और सर पर चढ जाएगा । इस लिए गांव वाले इस रुपए को नहीं लेना चाहते । और गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह नहीं देती । आज स्थिति यह है कि गांव के लोग शहरों की तरह भाग रहे हैं क्योंकि गांवों की स्थिति खराब होती जा रही है । जब वे शहरों का रहने का स्टेंडर्ड देखते हैं तो उन के मन में भी यह तमन्ना होती है कि वह भी अच्छा जीवन बिताएं, अच्छे घरों में रहें, स्लम्स में और गन्दी गलियों में न रहें । जो लोग गांवों में जरा पढ़ लिख जाते हैं वे शहरों की तरफ भागते हैं । जिस का परिणाम यह हो रहा है कि गांव उजड़ते जा रहे हैं, और इस का खेती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है । इस लिए मेरा गवर्नमेंट से विनम्र निवेदन है कि वह गांवों की गिरती हुई हालत की तरफ ध्यान दे ।

जो दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बना है उस में गावों को लिया जा रहा है, और उनको उजाड़ा जा रहा है । और गांव वालों को जो पैसा मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है । इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

गांवों में सड़कें भी बनानी चाहिए और इंडस्ट्रीज भी स्थापित करनी चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं होता । अभी जो सन् १९६२ और १९६३ जो कानफरेंसें हुई दिल्ली और बम्बई में, उन में शहरों के बारे में बहुत कुछ कहा गया , लेकिन गांवों के बारे में कुछ नहीं कहा गया । मैं चाहता हूं कि जो हाउसिंग फैसिलिटीज शहरों में दी जाती हैं वही गांवों में दी जाएं । जो फैसिलिटीज शहरों में लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप वालों को दी जाती हैं वे ही गांवों में भी दी जाएं । उनको आधा कर्जा मिले और आधी सबसिडी दी जाए । तीन हजार की आबादी का एक गांव बनना चाहिए और उन में सड़कों और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए । ऐसा करेंगे तभी गांवों की तरक्की होगी । केवल कहने से गांवों की तरक्की नहीं हो सकती ।

अब मैं कुछ एस्टेट आफिस की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । एरियर्स बहुत कुछ बाकी है । पबलिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ३२८३ हजार रुपए बाकी हैं सन् १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० के बारे में और उस में इजहार अफसोस किया गया है कि उस एरियर को वसूल करने की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जाती । पुराने मिनिस्टर साहिबान अपने बंगलों में रह रहे हैं और उनको हटाने की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है । लेकिन गरीबों को आप डंडे के जोर से हटा देते हैं । मेरे पास तस्वीरें हैं । कि अरजुन नगर और नीमरी के लोगों को किस तरह डंडे के जोर से हटाया गया । एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी तरफ मिनिस्टरों को हटाने की तरफ तवज्जह नहीं दी जाती ।

एक हाउसिंग कमेटी बनी है . .

**अध्यक्ष महोदय** : आप का वक्त हो लिया ।

**श्री मोहन स्वरूप** : मुझे कुछ और बातें कहनी हैं, दो तीन मिनट और लूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : आठ मिनटआप परसों ले चुके हैं और आठ मिनट आज भी होगए ।

**श्री मोहन स्वरूप** : मेरी प्रार्थना है कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाएअ, दो तीन जरूरी बातें कहनी हैं ।

एक हाउसिंग कमेटी बनी है । उसका मुद्दा यह था कि इस समस्या का अच्छी तरह से समाधान हो । लेकिन होता यह है कि उससे अलग एक एकोमोडेशन कमेटी बनी है यह कमेटी हाउसिंग कमेटी के अन्तर्गत ही है । मैं इसके बारे में इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि यह आपके द्वारा गठित की गई है । जो एकोमोडेशन कमेटी के प्रोसीडिंग्स होते है वे हाउसिंग कमेटी के सामने नहीं आते और वह जो चाहती है करती है । उसके प्रोसीडिंग्स कानफरमेशन के लिए भी हमारे सामने नहीं आते । मैं बहैसियत मेम्बर के यह चीज आपके सामने रख रहा हूं कि इसमें सुधार होना चाहिए अगर हाउसिंग कमेटी को ठीक तरह से चलाना है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसमें सुधार वह तो नहीं कर सकते और आपको यहां इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए था । यह चीज तो मेरे ताल्लुक है । आप मेरे पास आते । इस काम को मिनिस्टर साहब कैसे करेंगे ।

**श्री मोहन स्वरूप** : एकोमोडेशन कमेटी के प्रोसीडिंग कम से कम हाउसिंग कमेटी के सामने तो आते चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिए आप मेरे पास आएं ।

**श्री मोहन स्वरूप** : एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं फरनीचर के सिलसिले में । एक स्केल फरनीचर है, एक विल्ट इन फरनीचर है और एडीशनल फरनीचर है । केवल फरनीचर का किराया २४ रुपय है । लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो भी एडीशनल फरनीचर का काफी किराया लग जाता है । मैंने अपना स्केल फरनीचर हटा दिया है, लेकिन फिर भी मुझको २४ रुपया महीना देना पड़ता है । यह फरनीचर काफी पुराना हो गया है यह भी देखना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात तो वाकै बहूत जरूरी है ।

**श्री मोहन स्वरूप** : मैं संक्षेप में दो, तीन प्वाएंट और अर्ज करूंगा ।

सप्लाई आफ वाटर के बारे में मैं कहना चाहता था कि ३०३ ट्यूबवेल्स बने हैं जिनमें से कि २२३ ट्यूबवेल्स चालू और ८० बेकार पड़े हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इसकी क्या वजह है ?

होटल जनपथ की तरफ मैं सदन और मंत्रीमहादय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अभी तक उसके बारे में यह तय नहीं हो पाया है कि उसका स्टेटस क्या होगा ? कहा यह जा रहा है कि उसको किसी इंडिविजुअल को दिया जायगा । वैस्टर्न कोर्ट में कोई सज्जन हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, सुना जा रहा है कि यह उनको दे दिया जायगा । इस खबर से लोगों में बड़ा असन्तोष फैल रहा है । जब अशोक होटल मुनाफे पर चलाया जा सकता है तो जनपथ होटल को भी सरकार द्वारा मुनाफे पर क्यों नहीं चलाया जा सकता है ? उसको भी मुनाफे पर चलाया जा सकता है । इसलिए उसकी तरफ तवज्जह होनी चाहिए और इन होटलों के बारे में एक वाजे पालिसी होनी चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब तो माननीय सदस्य मेरी बात मान लें और अपनी बात खत्म कर दें ।

**श्री मोहन स्वरूप** : बस मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता था कि मकानों के ऐलाटमेंट के बारे में जो गड़बड़ चलती है वह बंद होनी चाहिये। अब होता यह है कि कहीं तो मकान बिना एप्लीकेशन के एलाट हो जाता है तो कहीं अर्जी देने पर भी मकान नहीं मिलता है। मुझे बतलाया गया कि एक पत्रकार जो कि एक सेक्रेटरी की मिसेज के मकान में रहता था और उसको हटाया जाना था इसलिए उसको दूसरा मकान दे दिया गया। उसको कम्पल किया गया कि वह उसको खाली कर दे। मैं चाहता हूं कि इस तरह की गड़बड़ियां न हों।

बंगाली कौलिनी के बारे में मैं अर्ज करूंगा .....

**अध्यक्ष महोदय** : अब तो बस ही कीजिये। श्री नवल प्रभाकर।

**श्री नवल प्रभाकर** (दिल्ली—करोल-बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान तिहाड़ गांव की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब से इस देश का विभाजन हुआ है और लोग गांव के अन्दर आकर रहे कई बार उनको आश्वासन दिया गया कि इस गांव का रिमौडलिंग होगा। रिमौडलिंग के सिलसिले में कई बार उसका बजट बना और तखमीना लगा और उसे ७ लाख से बढ़ा कर २७ लाख कर दिया गया लेकिन आज तक उन लोगों को बसाया नहीं गया है। मेरा माननीय मंत्री की सेवा में विनम्र निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें और विस्थापित भाइयों को बसाने की कृपा करें।

झील नजफगढ़ की ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। झील नजफगढ़ लगभग दस साल से भरी हुई है। कई बार इसका प्रयास किया गया कि इसका पानी किसी तरह से निकाला जाये। सारी विस्थापित बस्तियां इसके पास बस गई हैं और उनके बीच में से झील नजफगढ़ का नाला गुजरता है। अब सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से इसका काम चल रहा है लेकिन जब भी हम अपने इलाके के के लोगों से पूछते हैं और लो काम हो रहा है उसको देखते हैं तो पाते हैं कि उस काम की गति बड़ी मन्द है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें कुछ गति लायें, तेजी लायें ताकि यह काम शीघ्रता से पूरा हो जाय क्योंकि यह शहर और गांव दोनों के लिये लाभप्रद है। गांवों के अन्दर बहुत सी जमीन पानी से घिरी हुई है और शहर के अन्दर भी जहां जहां यह नाला गुजरता है एक गन्दगी और बदबू फैलाता हुआ जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्रीमन्, दिल्ली में ३६० गांव हैं। अब घटते घटते कोई २५० गांव रह गये हैं। जब गांवों की जमीन ऐक्वायर कर ली जाती है तो कुछ गांव उसके बीच में रह जाते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिये प्लाट्स डेवलप कर दिये जाते हैं। उनको बसाने के लिये भी योजनायें बनी हैं लेकिन जो गांव बीच में आ जाता है उसको स्लम डिक्लेयर कर देते हैं और फिर इन गांव वालों का जिनका कि पुश्तनी यह अधिकार है, उनके बाप दादा के समय से अधिकार चला आता है, सैकड़ों साल से जो यहां बठे हैं उनको वहां से हटाते हैं और उनको दूर किसी दूसरी जगह भेजते हैं। मेरा माननीय मंत्री की सेवा में विनम्र निवेदन है कि आप गांवों की जमीनें ऐक्वायर करें लेकिन जिस गांव की जमीन ऐक्वायर करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके फैलाव या प्रसार के लिए, तो कुछ जमीन आप छोड़ दें ताकि वे ऐसी जगह पर फिट हो सकें। वे लोग वहीं पर बस सकें। कई जगह देखा गया है कि वहां बहुत बड़े बड़े मकान बना दिये हैं और वह जो बेचारे गांव के लोग हैं वे असहाय अवस्था हो जाते हैं। न उनका कोई नक्शा पास करता है और न ही और कुछ प्रबन्ध होता है और लाचार हो

कर उनको परेशान हो कर वहां से हट जाना पड़ता है ।

श्रीमन्, गन्दी बस्तियों की जो योजना है यह काफी दिनों से चल रही है । लेकिन इसकी प्रगति भी बहुत ही मन्द है । माननीय मंत्री की सेवा में मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें और इसके काम में तेजी लाने की कृपा करें । यह सही बात है कि यह काम म्युनिसपल कारपोरेशन को सौंप दिया गया है और म्युनिसपल कारपोरेशन इसको देखती है लेकिन मैंने यह देखा है कि म्युनिसपल कारपोरेशन में भी एक अलग महकमा बना हुआ है । पहले तो यह है कि म्युनिसपल कारपोरेशन एक आटोनमस बाडी है और उसने आटोनमस बाडी में एक आटोनसम बाडी बना दी है जिसका कि अधिकार म्युनिसपल कारपोरेशन को भी नहीं है । इसलिए, श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि आप अपनी लेविल पर अगर सम्भव हो तो कोई कानूनी सुधार कीजिये क्योंकि हम तो आप को ही कह सकते हैं । इसलिए आप कुछ ऐसा इन्तजाम कीजिये ताकि इसमें प्रगति आये और जो गन्दी बस्तियां हैं, कुछ न कुछ लोग वहां से हटें या वहां पर ही कुछ डेवलपमेंट हो, विकासकार्य हो ।

झुग्गी झोपड़ियों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आजकल उसका एलाटमेंट चल रहा है । लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उसमें हरिजनों के साथ में भेदभाव बरता जा रहा है । हरिजनों और उनके अन्य साथियों को जो कि झुग्गियों में रहते हैं उनको ऐसी जगह दी जाती है जो कि पीछे की तरफ होती है । मेन रोड से पीछे की तरफ होती है । उनको वहां पर बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है । उनको यह कहा जाता है कि यहां लेना हो तो ले लीजिये वरना यहां से भी खाली करके चले जाइये । इसलिये मेरा निवेदन है कि म्युनिसपल कारपोरेशन और दिल्ली में जो और दूसरे मुहकमे हैं वह लोगों को एम्प्लाय तो कर देते हैं, खास तौर से जो फोर्थ क्लास लेबर हैं जैसे झाड़ू लगाने वाले मजदूरों को भरती तो कर लिया जाता है लेकिन उनके रहने का कोई इंतजाम उनकी तरफ से नहीं होता है । मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि स्थानीय निकायों (लोकल बाडीज) को तरफ़ से जब उनको नौकर रखा जाता है तो नौकरी देने के साथ साथ उनके रहने का इंतजाम भी कर देना चाहिए । नौकरी पर लगाने से पहले उनको बसाने का इंतजाम करें । चूंकि कोई इंतजाम नहीं किया जाता है और वे बेझुगी झोंपड़ी डालते हैं और फिर उनको तोड़ने का सिलसिला शुरु होता है । अब होता यह है कि अगर यह देखा जाता है कि कारपोरेशन के कर्मचारियों के साथ उनकी झुग्गी से हटाने और उसे तोड़ने के सिलसिले में नर्मी बरती जा रही है तो उस हालत में उनके साथ और दस और गैर आदमी आकर झुग्गो झोपड़ी डाल कर बैठ जाते हैं और इस तरह से यह सिलसिलस बढ़ता जाता है । इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में विनम्र सुझाव है कि लोकल बाजीज नौकरी देने से पहले कम से कम अपने यहां क्वार्टर्स बनाय जहां कि उनके आवास की समुचित व्यवस्था की जा सके ।

कम आय वालों के लिये जो आवास योजना है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जितना रुपया रक्खा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, अब उसमें से सुना है कि एक तिहाई काट दिय गया है । यहां दिल्ली में पहले ही मकानों की बहुत किल्लत है । ऐसी अवस्था में मैं मंत्री जी से कहूंगा और श्रीमन्, आपके द्वारा प्लानिंग कमिशन से भी कहा चाहता हूं कि वह इस कटौती को वापस ले लें और जो एक तिहाई की कटौती की है उसको हटा द ताकि मकान बनाने में असासानी हो सके ।

गांवों के अन्दर जो मकान बनाने की बात है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर जैसा कि मैंने कहा केवल २५० गांव ऐसे रह गये हैं जो कि देहात के अन्दर माने जा रहे हैं । धीरे धीरे गांव समाप्त

[श्री नवल प्रभाकर]

होते जा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री की सेवा में विनम्र निवेदन करूंगा कि वह देश के अन्दर बहुत सारे गांवों को डेवलप करना चाहते हैं । किन्तु मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने शहर के लिए एक मास्टर-प्लान तैयार कर लिया है, वैसे ही दिल्ली के देहात के लिए एक ले-आउट तैयार कर लिया जाये । आज नहीं तो दस, बीस, पच्चीस बरस बाद उन गांवों के डेवलपमेंट का प्रश्न आयेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अभी से हर एक गांव का लेआउट तैयार कर लिया जाये और उस ले-आउट के अनुसार ही उन गांवों का विकास आग चले और उस ले-आउट के अनुसार ही वे गांव बढ़, ताकि जब शहर बढ़ता हुआ चला जाये, तो वे उसमें फ़िट इन होते चले जायें और गांव वालों को दिक्कत न हो ।

**श्री बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह अर्ज़ करूंगा कि यहां पर झुग्गी-झोंपड़ियों का जो मसला है, वह एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक मसला है । इससे देश की मर्यादा टूटती है और मानवता के चरित्र पर कलंक लगता है । आज हम चीन वालों को बदमाश, दरिन्दे और पापी कहते हैं । क्यों ? क्योंकि वे हमारे देश में रहने वाले इन्सानों को खाना-बदोश बना जाते हैं, उनके घर लूट लेते हैं, आग लगा देते हैं, मकान तोड़ देते हैं । यह बुराई और चीन की इस बुराई के खिलाफ़ हम चीनियों को इन्सान-नुमा दरिन्दे कहते हैं । ऐसे मौके पर देश में कौमियत, वतनियत और देशभक्ति का जज्बा होना यकीनी है । लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, जो कि भारत का दिल और केन्द्र है, सरकारी कर्मचारी, कार्पोरेशन के कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी, जिस तरह काम करते हैं, विदेशी हमला-आवर भी उस बेदर्दी से नहीं करते होंगे । उन गरीबों के मकानों और झोंपड़ियों को वे बचा देते हैं, बीमार बच्चे-बच्चियों को बसीट कर बाहर डाल देते हैं, उनका सामान बाहर फेंक देते हैं और ले भी जाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान की जनता के दिमाग में यह ज़हनियत और कमजोरी आ जायगी, जब उनमें जुल्म को बर्दाश्त करने की आदत हो जायेगी, तो यह देश कभी भी विदेशी हमले का मुकाबला नहीं कर सकेगा ।

दूसरी बात यह है कि उन लोगों को देश की आज़ादी से क्या फायदा हुआ । उनको इन बड़े बड़े महलों से क्या फ़ायदा हुआ ? क्या हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के बाद उन ग़रीब लोगों का इस देश में इतना भी हक़ नहीं है कि वे कहीं पर झोंपड़ी डाल कर बैठ सकें ? आज अगर वे कहीं पर झोंपड़ी डाल कर बैठते हैं, तो उनके साथ दरिन्दों का सा सलूक किया जाता है ।

जो झोंपड़ियां अभी तोड़ी गई, उनमें ऐसी बच्चियां भी थीं, जिनको माता निकली हुई थी । अगर वे किसी मिनिस्टर, किसी बड़े आदमी, किसी एम० पी० या राजा-महाराजा, किसी नेता के बच्चे होते और उनकी झोंपड़ियों को तोड़-फोड़ कर उनको निकाला जाता और वे साये और दवा के लिये सिसकते तो पता चलता कि कितना अन्याय और जुल्म है । बापू ने कई साल तक इस देश को यह सबक सिखाया था कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ो । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि गोडसे उनकी हत्या कर के शायद उनका सिद्धान्त ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन हमारी लाड़ली सरकार ने इन पन्द्रह सालों में डंडे के ज़ोर से झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ कर गांधी जी द्वारा दिए हुए सबक को खत्म कर दिया है, गरीबों के दिलों की शक्ति और शान्ति को समाप्त कर दिया है और इस देश के लोगों के मनों को इतना दुर्बल और कमजोर बना दिया है कि वे कोई कदम नहीं उठा सकते ।

ये बड़े महल बनें या न बनें, इससे कोई मतलब नहीं है। बड़े महल भी बनाये जायें, यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कब ? जब हिन्दुस्तान के रहने वालों को सिर छिपाने को जगह मिल जाये। अगर बड़े बड़े महल बनाये जायें, अगर मिनिस्टर महोदय मीलों लम्बी-चौड़ी कोठियों में रहें और वे बिजली और पानी पर सैकड़ों रुपये खर्च करें, लेकिन गरीबों को उनकी झोंपड़ियों में भी रहने न दिया जाये, इस बात को किसी भी तरह मुनासिब नहीं ठहराया जा सकता है। सुना करते थे कि अगस्त्य मुनि तीन चुल्लू में समुद्र पी गए। लेकिन हमारे मिनिस्टर छः छः सौ रुपये की बिजली पी जाते हैं। लेकिन वह तो एक अलग बात है। जब एक तरफ वे इतना ज्यादा खर्च करते हैं, उनके लिए इतना ज्यादा खर्च होता है और दूसरी तरफ़ गरीबों के लिए रहने की कोई जगह नहीं है, तो फिर यह आजादी अधूरी आजादी है और यह आजादी के माथे पर कलंक का टीका है कि झोंपड़ियों में रहने वालों को उन झोंपड़ियों से निकाला जाये। उन लोगों के लिए कालोनीज बनाई जानी चाहिए।

जोरबाग रोड पर बागड़ से आये कुछ बागड़ी लोग पन्द्रह बीस साल से दुकान किया करते थे। वे आजादी से पहले वहां आबाद थे। उनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं था। जब वहां पर चारों तरफ कांटेदार तार लगा कर उनको वहां पर बैठने से रोक दिया गया है। वहां पर ऐसा मोर्चा बनाया गया है, जैसे चीनियों को रोकने के लिए मैकमोहन लाइन पर मोर्चा बनाया गया हो। वे गरीब लोग वहां पर अपनी रोटी कमाया करते थे, लेकिन अब वहां पर काम करने और सब्जी वगैरह बेचने से उनको रोक दिया गया है।

यह दिल्ली की बहुत गम्भीर समस्या है। इसके लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर, पंडित नेहरू, के मकान पर धरना भी देना पड़ा और झोंपड़ी-झुग्गी वालों को वहां पर ले जाकर बिठाना पड़ा। जेल भी गए, लेकिन चीन के हमले और इमर्जेंसी की वजह से उस आन्दोलन को वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इसको कितने दिन तक दबायेगी। असल में यह दबेगा नहीं। यह दोनों तरह से हानिकारक है। अगर सात लाख झुग्गी-झोंपड़ी वालों की आत्मा को कुचल कर उनको ख़ानाबदोश बना दिया, तो इस देश की मर्यादा टूटेगी और यह देश मानहीन लोगों का देश बनेगा। अपनी मर्यादा को कायम रखने वाल देश नहीं बनेगा। और यह बात नहीं हो सकती। आख़िर यह बापू का देश है। वे लोग कब तक जुल्म को बर्दाश्त करेंगे ? अगर वे कभी अपने हक और मानवता के लिये उठेंगे, तो फिर देश में एनार्की फैलेगी और फिर सरकार की तरफ से कहा जायेगा कि उनको डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज के तहत पकड़ लो। डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज के तहत तो उनको पकड़ना चाहिए, जो हिन्दुस्तान, मादरे-वतन और राष्ट्रपिता बापू के हृदय और मन के राजाओं को उखाड़ते हैं। बापू नें कहा था कि मैं दरिद्र को राम के रूप में देखता हूं। इसलिए दरिद्र-नारायण को उखाड़ने वालों पर मुकदमा चलना चाहिए। जो उनको तबाह और बरबाद करते हैं, वे मुजरिम हैं। जिस तरह चीन जुर्म करता है, उसी तरह यह महकमा भी जुर्म करता है जो कि गरीबों को उनकी झोंपड़ियों से निकालता है।

जहां तक झुग्गी-झोंपड़ी वालों का ताल्लुक है, उनको कतई नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हर कोलोनी और हर जगह पर उनको जगह दी जानी चाहिए। इस सिलसिले में हिसाब-किताब की बात कही जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो बेचारे गरीब और ख़ानाबदोश लोग हैं, जो हजारों सालों से दलित और समाज के सताये हुए हैं, अगर उनके पास हिसाब किताब होता, तो वे अपनी लूट-खसूट कैसे करने देते, उनका शोषण कैसे चलता। हिसाब-किताब में वे बेचारे कमजोर हैं।

[श्री बागड़ी]

हिसाब-किताब वे नहीं रख सके, यह कह कर उनको उजाड़ा जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह हिसाब-किताब का सिलसिला वह बन्द करे और वह ऐसे कायदे बनाये कि जिसके पास जगह नहीं है, जहां पर वह बैठा है, उसको उजाड़ा न जाए।

इसके बाद में कहना चाहता हूं कि हम इतिहास के साथ एक बहुत बड़ी बेवफाई कर रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसी बात नहीं हुई। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे। जहां पर वह शहीद हुए, जिस मकान में वे रहते थे, वहां पर उनकी यादगार बनाने के बारे में मैंने बारहा प्रधान मंत्री महोदय से ख़तो-किताबत की है। उन्होंने लिखा है कि बिड़ला साहब उस जगह को प्राइम मिनिस्टर को रहने के लिए तो देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने ऐसा आफ़र किया था, लेकिन मैंने इन्कार कर दिया। जब बिड़ला साहब से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हां, मैंने प्राइम मिनिस्टर के रहने के लिए तो जगह देने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, आप और यह शहीदों के इतिहास से पूरी तरह वाकिफ़ है। जब शहीदों के इतिहास को भुलाया जाने लगा, तो देश और कौम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमारे मिनिस्टर साहब बिड़ला साहब के साथ ख़तो-किताबत करते, एक दो लाख रुपया ज्यादा लग जाता, उस जगह को एक्वायर करके वहां पर महात्मा गांधी का स्मारक और शहीद होने की जगह पर यादगार बनाते, तो अन्याय और फिरका-परस्ती के खिलाफ़ बापू का जो खून बहा था, उससे देश को प्रेरणा मिलती और वह आगे बढ़ता। लेकिन देश को क्या कहें, इस पार्लियामेंट को कबरिस्तान बनाया जा रहा है और यहां पर मोतीलाल जी का बुत लगाया जा रहा है, महात्मा गांधी का नहीं। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं है कि यहां पर पंडित मोतीलाल नेहरू का बुत लगता है या और किसी का। कुछ खूबियां और ख़सूसियत देख कर और नेशन के लिए किये गये त्याग को देख कर ही ऐसे बुत लगाए जाते हैं। ठीक है, उनका भी त्याग है। लेकिन जहां पर महात्मा गांधी का बुत नहीं लग सकता और नहीं लगा, वहां पर यह बुत लगाया जा रहा है। अगर यहां पर किसी का बुत लगाना था, तो उन शहीदों में से किसी का बुत नस्ब किया जाता, जिन्होंने नेफ़ा और लद्दाख की पहाड़ियों पर मादरे-वतन की सेवा करते हुए, मादरे-वतन की हिफाजत करते हुए जिन्दगी दी। अगर उनमें से किसी का बुत लगता, तो कौम में शिन्दगी आती। लेकिन यहां पर तो कबरिस्तान बनाया जा रहा है। चाहे किसी प्राइम मिनिस्टर का बाप हो, चाहे कोई और हो, यह हमारे देश के लिये अच्छा नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इस बारे में कुछ एहतियात तो करनी चाहिए। पार्लियामेंट में और उसके एहाते में जो चीज़ लगनी है, उसके बारे में अगर माननीय सदस्य मेरे पास आकर बात करें, तो अच्छा होगा। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यहां पर जो चीज़ लगाई जाती है, वह स्पीकर की इजाजत से ही लगाई जाती है।

**श्री बागड़ी** : इस बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इशारा किया था .....

**अध्यक्ष महोदय** : किस की इजाजत से लग रहा है, इसको भी आपको देख लेना चाहिये। बिना स्पीकर की मर्जी के कोई भी चीज नहीं लगाई जा सकती है। अगर आपको इस पर कोई एतराज़ है तो आप मुझ से आकर बात कर सकते थे और मैं आपको सारी बात बतला सकता था।

**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। जो बुत लग रहा है

वह इसलिए नहीं लग रहा है कि वह किसी के पिता थे। वह इसलिये लग रहा है कि उनका बड़ा जबर्दस्त असैंबम्ली के साथ सम्बन्ध था, पार्लियामेंटरी लाइफ के साथ सम्बन्ध था। यह भी हर कोई जानता है कि इस हाउस के आप मालिक हैं, पार्लियामेंट हाउस के प्रिसिक्ट्स के आप मालिक हैं मेरे खयाल में जो इनका रिमार्क था मोतीलाल जी के मुताबिक, हय ठीक नहीं था। वह हमारे देश के एक जबर्दस्त नेता थे और उनकी बहुत भारी कुर्बानी थी। उनके मुताल्लिक मेरे ख्याल इस में तरह की बातें कहना जैसी कि माननीय सदस्य ने कही है, बायसे अफसोस है। मुनासिब यह होगा कि इस किस्म के रिमार्क्स को प्रोसीडिंग्ज में से एक्सपंज कर दिया जाए। वह एक बड़े जबर्दस्त नेता थे और हिन्दुस्तान को आजाद करने में उनका बड़ा जबर्दस्त हिस्सा था।

**श्री बागड़ी** : गांधी जी से ज्यादा हिस्सा तो नहीं था .....

**अध्यक्ष महोदय** : आप उसी बात पर जिद कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है (*Interruption*) मुझे इजाजत है कि मैं कुछ कह सकूं ?

**श्री बागड़ी** : जी हां।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझसे पहले जो स्पीकर साहबान थे, उन्होंने दो व्यक्तियों के बुत लगाने की मंजूरी दी थी। एक मोतीलाल जी नेहरू के बुत की और दूसरे लाला लाजपत राय जी के बुत की जो पंजाब के थे। उनका फैसला यहां हो चुका। अब अगर आपको इसके बारे में कोई शिकायत है तो आप मेरे साथ आकर बहस कर सकते हैं और मुझे अपना एतराज बता सकते हैं। मैं आपको कागजात दिखा सकता हू और दूसरी चीज आपके सामने पेश कर सकता हूं। अगर आपको यह मालूम न हो तो इसके बारे में आप मुझ से पूछ सकते हैं।

जहां तक इस अहाते का ताल्लुक है, स्पीकर की मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं लग सकती है। यह बात कहना कि प्राइम मिनिस्टर के पिता का लग रहा है, ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री के पिता होने के बिना मोतीलाल जी का सियासत में, पार्लियामेंटरी लाइफ में और फ्रीडम स्ट्रगल में जो हिस्सा था, उसको भी देख लिया जाना चाहिये। इस तरह से मुकाबले शुरू करना कोई मुनासिब बात नहीं है। मैं यह नहीं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है, उसको निकाल देना ठीक होगा। लफ्ज वाकई अफसोसनाक हैं। मगर मैं उचित नहीं समझता हूं कि उनको निकालने की जरूरत है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (बिजनौर) : आपने कहा है कि आप से पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने यह निर्णय लिया था कि पंडित मोतीलालनेहरू जी और लाला लाजपतराय जी के स्टेचू यहां पर लगा दिये जायें। लेकिन सदस्यों को पत तब लगा जब यहां पर उनके बनने की तैयारी होने लगी। उससे पहले सदन में या समाचार पत्रों के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली थी। इसलिये यहां इसकी चर्चा आई। अगर पता लग जाता तो अच्छा होता

**अध्यक्ष महोदय** : आपने उस दिन भी एतराज किया था लेकिन मैं खामोश रहा था। आप सब जानते हैं कि इस अहाते के अन्दर स्पीकर की आखिरी अथौरिटी है। आपने इतना कष्ट भी नहीं किया कि मेरे साथ आकर बैठते और बात करते। बिना ऐसे किये आपने यहां पर नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी। मेरा एतराज यह है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। मेरे आने से पहले इसका फैसला हो चुका है कि ये दो बुत यहां लगाये जायें, मोतीलाल जी का और लाला लाजपत राय का।

[अध्यक्ष महोदय]

इस मामले में एक आदमी की एक राय और दूसरे की दूसरी राय हो सकती है । लेकिन इसका इलाज यह है कि आपस में हम मिल कर इस पर विचार कर लें। गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है । जो सोसाइटी यहां पर एक असें से बनी हुई है वह इस बात के लिये जोर देती आ रही है कि लाला लाजपत राय का बुत लगाने की उसको इजाजत दी जाए । उसका कहना है कि तमाम पब्लिक की यह इच्छा है कि वह काफी देर से बुत बनवाने की इंतजार में हैं । अगर आपका कोई एतराज हो तो आप मेरे पास आइये, मैं आपको समझा दूंगा कि किन आदमियों की इच्छा है, कौन मेरे पास आते हैं ।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है और इस अहाते का ताल्लुक है, उसके बारे में आखिरी अथारिटी स्पीकर की है । बिना इसका खयाल किये हुए नुकताचीनी करना शुरू कर देना और यह कहना शुरू कर देना कि प्राइम मिनिस्टर के बाप की लगा रहे हैं, दुरुस्त नहीं है । मोतीलाल जी का स्थान नेहरू का बाप होने के अलावा और भी हमारे पालिटिक्स में है उनके लिए हमारे दिलों में इसलिए इज्जत नहीं है कि वह जवाहरलाल जी के पिता थे ।

**श्री बागड़ी** : मैं आप की बात मानता हूं मगर मैं खन्ना साहब ने जो कुछ कहा है, उस का जवाब देना चाहता हूं । वैसे मोतीलाल नेहरू जी की ताजीम हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे देश भक्तों से कम नहीं है । बहुत से देश भक्त हमारे देश में हुए हैं । उन की ही सब से ज्यादा देश भक्ति थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है । उन्हीं में ही कोई खास विशेषता थी, यह भी नहीं .

**अध्यक्ष महोदय** : इन्हों ने नहीं कहा है कि उन से ज्यादा किसी और की नहीं थी ।

**श्री बागड़ी** : वह यह कह रहे थे कि इस तरह की बात जो कहता है, उस को शर्म आनी चाहिए । मैंने तो ऐसी कोई शर्म की बात नहीं कही है । मैं देश भक्तों की बड़ी ताजीम करता हूं । जो साधारण कोटि का देश भक्त भी हो गुजरा है, उसकी भी मैं इज्जत करता हूं । अगर शहीदों की शहादत को मैं भुला दूं तब तो मुझे शर्म आए । मैंने तो उनकी शहादत को नहीं भुलाया . . .

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस को छोड़िय और जो कुछ आप को कहना हो कहिये ।

**श्री बागड़ी** : डिफेंस कालोनी के अन्दर पहले फौजियों और जो रिटायर्ड फौजी थे, उनके लिए जगह दी गई थी । अब वहां आम आदमी भी जमीन खरीद सकते हैं । इस का नतीजा यह हुआ है कि पैसे वाले लोग ही उस जमीन को खरीद रहे हैं और जो फौजी हैं, और जो रिटायर्ड फौजी हैं, वे वैसे ही रह जाएंगे । मेरा सुझाव यह है कि इस की बन्दी की जाए ।

आज कल महंगाई बहुत अधिक है । दिल्ली "ए" क्लास सिटी है । जो लोग यहां पर दो सौ रुपया माहवार पाते हैं, उन से किराय के ४५ रुपय काट लिये जाते हैं । यह बहुत बड़ी रकम है । मैं अर्ज करूंगा कि दो सौ तक जिन मुलाजिमों की तनखाह है, उन से यह रकम किराये की सूरत में नहीं काटी जानी चाहिये ।

अब एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा । देश में एमरजेंसी है और आज के हालात का यह तकाजा है कि खर्च कम किया जाए । जो बिजली पानी वाला सवाल आया था, उस के लिए मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं । कई मिनिस्टर तो उस बात को ले कर छटपटा उठे थे । मेरा सुझाव यह है कि मिनिस्टरों को छोटी कोठियां दी जानी चाहिये । आप देश के भूखे तथा नंगे लोगों से उनके मुंह से एक एक

दाना और एक एक बूंद मांगते फिरते हैं। क्यों मिनिस्टर लोगों की कोठियों में खर्च कम नहीं आप करते हैं। यह जो पानी बिजली, फर्निचर का खर्च है, यह भी कम होना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि यह सब खर्चा उनको अपनी जेब से देना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वाल्मीकी।

**श्री बाल्मीकी** (खुर्जा) अध्यक्ष महोदय:—

**अध्यक्ष महोदय** : वह शायद उम्मीद नहीं करते थे कि उन को वक्त मिलेगा।

**श्री बाल्मीकी** : निर्माण, आवास, सम्भरण तथा पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में आप ने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

पुनर्वास मंत्रालय को इस निर्माण-आवास मंत्रालय के अन्दर विलीन कर दिया गया है और उस काम को माननीय मंत्री जी समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। वह समझते हैं कि पुरुषार्थी भाइयों की समस्या हल हो गई है। मैं मानता हूं कि वह बहुत कुछ हल हो भी गई है और उसका श्रेय उनको मिलना चाहिये। लेकिन आप के द्वारा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे पुरुषार्थीभाई जो गरीबों की तरह रह रहे हैं, जो बगैर जायदादों के रहे हैं, विशेषकर हरिजन, उनके पुनर्वास का काम "न" के बराबर ही हुआ है। मैं यहीं नहीं, देश के अनेक भागों में जाने के बाद और अभी पंजाब के अन्दररूनी भागों में भी गया था, देखा है कि बलूचिस्तान, सिंध या फ्रंटियर जहां से कि हमारे मंत्री महोदय आते हैं वहां से भी बहुत से पुरुषार्थी भाई आये हैं, विशेषकर हमारे हरिजन लोग, जिन के लिए न नौकरियों का प्रबन्ध हुआ है और न रहने का, इस लिये कि उनके पास कोई जायदाद नहीं थी। कुछ कालोनीज यहां बनाई गई हैं, लेकिन उन कालोनीज में भी इस तरह के ज्यादातर लोगों को नहीं बसाया गया, हालांकि वहां पर बहुत काफी लोग बसाये गये हैं। यह ठीक है कि इस अवसर पर जब कि हमारे देश पर चीन के हमले से स्थिति बड़ी विषम है, मैं और तरह की विवाद ग्रस्त बातों को नहीं उठाना चाहता लेकिन फिर भी मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जो देश का विभाजन हुआ, वह देश के लिये बड़ी दुःखदायी घटना थी। हमें बापू जी को हाथ से खोना पड़ा। वह भी अत्यन्त दुःखजनक घटना थी। हालांकि यह बात भी सही है कि अनेक हमारे भाई ऐसे हैं, विशेषकर सफाई का काम करने वाले बाल्मीकी भाई, जिन को यहां लाया गया और अवसर भी दिया गया, लेकिन आज भी हमारे काफी भाई पश्चिमी पाकिस्तान में रह गये हैं, जिनके खत आते रहते हैं और उन में उन की दुःखभरी घटनायें वर्णित रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बात विशेषकर हमारे इतिहास में एक याद बन कर रह जाती है कि अभी उन को हटाने का काम कुछ हद तक ही किया गया है। उनके रिपैट्रिएशन का काम बीच में छोड़ दिया गया है। जब भी इस विषय में सलाह पाकिस्तान सरकार से की गई, उस सलाह के अन्दर भी जहां तक उन के धर्म को जबर्दस्ती बदलने का सवाल है या किसी तरह से उनको पाकिस्तान में जबर्दस्ती रखने की बात है उन की इच्छा के विरुद्ध, मैं कहना चाहता हूं कि उस ओर कम ध्यान दिया गया है उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस को जरूर समझेंगे कि आज भी अनेक इस प्रकार के लोग हैं जिन की पत्नियां तो यहां हैं और आदमी वहां हैं या पत्नियां वहां हैं और आदमी यहां हैं। उन को ठीक तरह से लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है।

जहां तक सफाई पेशा और बाल्मीकी भाइयों की बस्तियों के बसाने का सवाल है,

[श्री बाल्मीकि]

मैं समझता हूं कि यह काम बहुत उदासीनता से किया गया है, न के बराबर किया गया है। मैं यह दोष अवश्य इस मंत्रालय के सिर पर मढ़ना चाहता हूं। यहां पर कोई भी कालोनी बन हो, चाहे विनोबा कालोनी हो या कालका कोलोनी हो, जो भी क्वार्टर बनाये गये वह जो हमारे भाई हैं उन लोगों के हाथ नहीं पड़े बल्कि दूसरे रिफ्यूजी भाइयों को दिये गये। यहां तक कि विनोबा कालोनी के अन्दर एक प्रकार का क्रीड़ा स्थल बनाया गया, और एक कम्यूनिटीहाल बनाया गया, कालका कालोनी के अन्दर भी उसी प्रकार से बनाया गया, लेकिन वह हमारे भाइयों के विरुद्ध दूसरों को दे दिया गया जबकि खास तौर से उनके काम के लिये हो, उनके सार्वजनिक कार्यों के लिये हो, वे स्थान बनाये गये थे, लेकिन वह नहीं हुआ। बावजूद इस बात के कि हम को हर तरह से इसके योग्य समझा जाता है दूसरों से ज्यादा, लेकिन उनको नहीं दिये गये। जिन लोगों को सदियों के प्रयास के बाद योग्यतम समझा गया है उनमें इतनी योग्यता है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपना काम संभाल सकें, वे सिर्फ आपकी सहायता चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात पर बड़ा अफसोस होता है कि यह सहायता हमें नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री जी सहृदयता के साथ सब की बातों को सुनते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे विशेषकर इन बातों की तरफ ध्यान देंगे और हमारी समस्याओं के हल में सहायता देंगे।

जहां तक इवैक्वी प्रापर्टी का सवाल है, हो सकता है कि जो लोग शक्तिशाली थे, जो लोग धन वाले थे उनको किसी प्रकार से कम्पेन्सेशन के रूप में जमीनें मिलीं चाहे वे रहने की रही हों या खेती की रही हों या आवास आदि की रही हों। हो सकता है कि इस तरह के लोगों को अधिक सहायता प्राप्त हो सकी हो जो कि धन आदि के रूप में अपना काम कर सकते थे। लेकिन जहां तक हरिजनों का सवाल है, विशेषकर बाल्मीकी भाइयों का, जो कि उन स्थानों पर बैठे थे, उनको जमीनें नहीं मिलीं। मैं अभी पंजाब के दौरे पर गया था, और वहां से लौट कर आया हूं। वहां पर सब जगहों पर ऐसी शिकायत आई है कि जिन अहातों के अन्दर जिन कटरों के अन्दर या मोहल्लों के अन्दर, या उन जमीनों के ऊपर जो कि देहातों या शहरों में थीं, जो लोग बीस बीस साल से, चालिस चालिस साल से, साठ साठ साल से हरिजन बैठे हुये हैं वहां उन में से बहुत कम लोगों को जमीनें दी जा सकी हैं। मगर इस के लिये न किसी प्रकार की सहायता सरकार की ओर से होती है और न विभाग की ओर से होती है। इस प्रकार के झगड़े सरकार के सामने आये भी हैं।

जब माननीय पन्त जी जिन्दा थे, सेंट्रल हरिजन वेलफेअर बोर्ड के अन्दर यह बात आई थी और यह कहा गया था कि अगर जो हरिजन इवैक्वी प्रापर्टी पर रहते हैं, और एक तरह से उनका कब्जा भी हो, वे धीरे धीरे किश्तों में धन दे दें, और वे दे भी सकते हैं, तो दस हजार रुपये से कम का जो प्रापर्टी है वह उन्हें प्राप्त हो जायेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि उन पर बोलियां लगाई जाती हैं। जब बोलियां लगाई जाती हैं तो जो धन वाले हैं, जो पैसा वाले हैं या जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि हर एक को खुश कर सकते हैं वे उनको खरीद ले जाते हैं। इस बारे में एक यह भी शिकायत है कि इस तरह के लोग बड़ी बोली बोलकर अधिक हिस्सा ले जाते हैं और हरिजनों को वे जमीनें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हरिजन इन इवैक्वी प्रापर्टीज के अन्दर बैठे हुये हैं, चाहे वे आवास की हों या किसी और प्रकार की हों, इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि वे जमीनें उनको ही मिलें। यह एक गम्भीर

सवाल है जिसकी ओर हम को ध्यान देना चाहिये ।

आज हमारे देश में स्थिति यह है कि हमारा देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है । हमने समाजवाद को अपनाया है, आज हम समाजवादी ढांचे से पार हो रहे हैं । चाहे हम पर कोई चीनी खतरा ही क्यों न हो लेकिन जो हमारा मन्तव्य है, जो हमारा ध्येय है वह आज भी जारी है । समाजवाद का एक ही उद्देश्य होता है कि उसके अन्दर जो रहने के साधन हैं, खाने पीने के साधन हैं और जो सम्पत्ति प्राप्त करने के साधन हैं वे सामान्यतया ऐसे हों कि वे उन लोगों को भी प्राप्त हो सकें जिन्हें कभी प्राप्त नहीं हुये हैं । जो सदियों से भूखे रहे हैं और समाज की सेवा करते रहें हैं, उन्हें जमीनें प्राप्त हो सकें । मैं इस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मैं माननीय मंत्री महोदय को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार वर्क्स हाउसिंग मंत्रालय में प्रतीत होता था उसमें कमी हुई है । इस तरह के भ्रष्टाचार करने वालों को चाहे वे इंजीनियर हों या कोई भी हों, आड़े हाथों लिया गया है । लेकिन मैं विशेषकर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मंत्रालय के अन्दर जो भ्रष्टाचार की जड़ है वह ठेकेदारी प्रथा है । उसकी वजह से जो भ्रष्टाचार होता है उसको समाप्ति की ओर ले जाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे सरकारी ढंग पर किसी दूसरे आधार पर । मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में विशेषकर जो हमारी कोआपरेटिव सर्विस सोसायटीज हैं उनकी सहायता ली जाय और प्रोत्साहन दिया जाये । यह वायदा भी किया गया था कि धीरे धीरे यह ठेके सहयोग के आधार पर उन लोगों को भी दिये जायगे जिन से साधारण जनों का सहयोग हम को प्राप्त हो सके । मैं विशेष रूप से आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज हम समाजवादी समाज की बात करते हैं, उसके ऊपर बार बार ध्यान देते और दिलाते हैं, विशेषकर हमारी आवास समस्याओं की ओर इतना ध्यान उस दृष्टि से नहीं दिया जाता है लेकिन यह बात ठीक है कि आवास का प्रश्न एक बहुत जटिल प्रश्न है । गन्दी बस्तियों के बारे में और झुग्गी झोंपड़ियों के बारे में दूसरे साथियों ने भी प्रश्न उठाया है कि इसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार इस ओर ठीक से ध्यान दिया जाना चाहिये, जिस प्रकार बेरहमी से झुग्गी झोंपड़ियां गिराई जाती हैं उस प्रकार से जुल्म नहीं होना चाहिये । वे लोग जहां पर रहते हैं, जिस आराजी पर रहते हैं, वहीं पर उन्हें बसाने का प्रयत्न किया जाये । मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि झुगियों के आवास या सफाई पेशा लोगों के आवास की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है । यह काम बहुत मन्थर गति से चल रहा है और राज्य सरकारें भी इस ओर बहुत काम नहीं कर रही हैं । इधर तेजी बरती जानी चाहिये ।

आप रफी मार्ग पर संसद सदस्यों के लिये एक हास्टेल बनाने जा रहे हैं । वहां पर आप विशेष कर एक गोष्ठी क्लब बनायेंगे जहां पर आमोद प्रमोद और आनन्द विहार होगा । लेकिन मैं नहीं समझता कि जो भंगी भाई वहां चालीस सालों से रह रहे हैं उनका क्या होगा । जिन मेम्बरों के लिये वे बनाये जायेंगे उनके पास कार भी हो सकती है, दूसरे साधन भी हो सकते हैं, उनको आप कहीं दूर भी बसा सकते हैं । लेकिन इन गरीब भाइयों को उखाड़ कर समाजवादी समाज का आधार नहीं आ सकेगा । समाजवादी समाज का आधार यह है कि जो लोग बीच में रह कर सुबह से शाम तक सेवा करते हैं उन को न उखाड़ा जाए । माननीय मंत्री जो स्वयं जानते हैं, मैंने उनसे बातें की हैं, कि उन

[श्री बाल्मीकि]

लोगों की क्या कठिनाइयां हैं। इस अवसर पर उन लोगों को उखाड़ा न जाये, उनको दूर न भगाया जाये। उनको जो दूर भेजा जा रहा है जिससे कि वे कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक उनको बसाने का प्रश्न है, गन्दी बस्तियों के लिहाज से इस आवास की योजना में उनको कम स्थान दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अब इस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान आप के द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे भंगी भाइयों के लिये आवास बनाये जायें, वे दूर न भेजे जायें। इस बात की मिसाल हमारे दिमागों में रहेगी कि संसद सदस्यों को चूंकि दूर बसाया जा सकता है इसलिये गरीब लोगों को उनकी जगहों से उखाड़ कर कष्ट में न डाला जाये।

**श्री कछवाय** (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था, मैंने भी नाम दिया था।

**अध्यक्ष महोदय** : नाम तो है, लेकिन वक्त नहीं है।

**श्री कछवाय** : मैंने तीन चार रोज से नाम दिया हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : नाम तो है आपका और भी कई नाम हैं, लेकिन वक्त नहीं। इस वक्त तो आपको मौका नहीं दिया जा सकता।

**श्री कछवाय** : मैंने काल अटेंशन नोटिस दिया था और मुझे बतलाया गया था कि तुम इस पर बोल सकते हो।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपकी पार्टी का कोई मेम्बर इस पर बोला है?

**श्री कछवाय** : जी हां, लेकिन मैंने अरजेंट नोटिस दिया था और मुझे सेक्रेटरी महोदय द्वारा सूचना मिली थी कि मुझे समय मिलेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन आपकी पार्टी को मौका तो दिया गया, अब अगर उस ने दूसरे मेम्बर को खड़ा कर दिया तो मेरा क्या अख्तियार है। अब तो मैंने मिनिस्टर साहब को बुलाया है, आप फाइनेंस बिल पर बोल लीजियेगा।

**The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna)**: Mr. Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members who have taken part in the debate and made valuable suggestions. Within the time at my disposal, it may be possible for me to deal with every particular suggestion that has been made, but I do wish to tell them that every suggestion that has been made shall be examined and whatever appropriate action can be taken shall be taken.

**Shri D. N. Tiwary** (Gopalganj): Also the hon. Minister may inform the Members concerned.

**Shri Mehr Chand Khanna**: I may even write to the Members concerned about certain points that they have raised. I shall try to do that. I am also grateful to the hon. Members who made appreciative references day before yesterday to my work in the Ministry of Rehabilitation. It gives one very great encouragement. After all these years, for one who has tried to do his work honestly and conscientiously, there is an appreciation from one's own colleagues.

Sir, this Ministry is now no longer the Ministry of Rehabilitation of which I used to be in-charge and was in-charge for a period of about 15 years. The name of this Ministry is, the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation. Apart from that, in this Ministry, we deal with printing, publication and stationery. Then, we used to have the Supplies Department which is no longer with me now. Dr. Singhvi made a reference about it day before yesterday, enquiring why was this Department being taken away from this Ministry no concern of mine? But I do say that it has passed into very tried and experience hands and

full justice shall be done to the work of this Ministry, I have only one regret and that is that I had to part with my hon. friend and colleague, Shri Jaganatha Rao and during the short period that he was with me, he did very good and valuable work and made very valuable contribution. We even deal with Boilers and Explosives, not explosives inside the House, but explosives outside. Then, we also deal with....

**Mr. Speaker:** We deal with them outside. We create them here.

**Shri Mehr Chand Khanna:** We also deal with some public undertakings like the Ashoka Hotel, the Hindustan Housing Factory and the National Building Construction Corporation. It is a Ministry which, at one time, was called a service Ministry. We have tried to serve and do our level best. But today I propose only to deal with two or three major aspects of this Ministry.

I shall first go to housing. There are two types of housing that we deal with: one is the social housing and the other is the direct housing programme of this Ministry which we undertake through the Public Works Department. When, I refer to the social housing, I have in my mind the subsidised industrial housing scheme, the slum clearance, the jhuggi-jhupri scheme and low income group scheme, rental housing and rural housing. These schemes are of very great importance. These schemes were launched a few years ago. Basically, these schemes are very sound and they are in the best interests of the country and the population in different spheres, whether you call it rural population, whether you call it slum dweller, whether you call a person who is an industrial worker or who lives in rental housing. We cannot build a house without money. We can do many things without money, but for housing, money is needed. Whether I purchase land, whether I develop a site, whether I have electricity or water, it is essential that money should be there. When these housing schemes were formulated in the First Five Year Plan, there was an allocation to the extent of 35 per cent for housing. In the Second Plan it came down to 19 per cent and in the Third Plan it came further down to 15 per cent. It is an irony that while on one side the population of the country has gone up, during the last ten years between the period 1951 to 1961, there has been a growth of over 21 per cent in the population of the country, the allocation under housing in the three successive Plans has been cut down from 34 per cent to 15 per cent, that is more than half.

**Shri A. P. Jain** (Tumkur): That is our complaint against you.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I was there with you at that time. You have had no complaint against me. I was your adviser. That is what you told me. You paid me a compliment.

That has been the position. The reasons may be quite justified. I do not say there were no reasons, that the planners who drastically cut down the Plan allocations under housing gave housing only the same amount of importance or priority that it deserved. But the fact remains that money was highly inadequate and during this period, though we have been able to spend about Rs. 170 crores on housing, though we have been able to build over 2,55,000 houses. If I am asked, "are you fully satisfied with the performance", I am sorry to admit that I shall have to say, 'No'. We should have done better because if an average man is to have shelter and if the basic fundamentals of a socialistic pattern of society are food, clothing and housing—I shall not refer to the fourth priority as my hon. friend, the former Minister referred to, and my reasons are quite obvious, my age, and I will not.....

**Shri A. P. Jain:** Age is also deceptive.

**13.17 hrs.**

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

**Shri Mehr Chand Khanna:** I will not refer to that priority. But in a socialistic pattern of society, I do concede housing, food and clothing—are three basic fundamentals of our society. Attention has been paid to food and clothing. But the same attention has not been paid to housing. When I took charge of this Ministry, about 11 months ago, I went round various States and had personal discussions with my colleagues in the Housing Departments. After having analysed the problem, we called a conference of the Housing Ministers. But, as my misfortune would have it, it was timed with the Chinese aggression or the invasion on India. The result was that although we thought that with the money that we have and the targets that we wish to achieve, I should be able to convince the Planning Minister and Finance Minister, on account of the Emergency and the difficulties with which the country was suddenly faced, we could not get any further allocation. In fact, our allocations were further cut. I have no grouse on that account, because I honestly believe and I do concede that if this country has to remain strong, defence is our first requirement, and for the sake of defence, anything else and everything else can wait and should wait. And that is my experience as one who has lived on the frontier for over a period of fifty years. I feel that if the country has to be strong—and it must be strong to face aggression—perhaps, we may have to face many more cuts. But, as the Housing Minister I do have a grouse that while in other cases, perhaps, the allocations are being increased, in my case, even in the case of industrial housing, which is a part of production—because if industries have to be set up, then industrial workers have to be provided with accommodation, and unless we provide them with accommodation, I am afraid that we cannot step up our target of production to that extent—the allocations are cut. I do hope that my former colleague who has now gone to the Ministry of Economic and Defence Co-ordination which is now in charge of production, will take this up with his Minister and see that if he wants to step up production and set up industries, he has to find money for the construction of industrial houses.

We have taken a few steps, even in this difficult period, to find money, if we can, and step up our construction programme or even keep up to the original level. We get allocations under two heads for housing. One is the plan allocation which is provided in the Third Plan or in any plan, and the other is the money that we get from the LIC. Of the allocation of about Rs. 180 to 190 crores for housing in the Third Plan, we get Rs. 60 crores from the LIC. Last year we got only Rs. 6 crores from the LIC as against Rs. 10 crores. In Bombay, where we had the Second Housing Ministers' Conference, we invited the chairman of the LIC, and he was kind enough to tell me that he would make up the gap. So, instead of getting Rs. 10 crores this year, we shall be getting Rs. 14 crores, that is, Rs. 4 crores extra.

The second thing I feel—and the House has also expressed itself perhaps directly or indirectly—is about the setting up of a Central Housing Board. That is laid down in the Plan, and the Plan has been accepted by Government and by Parliament. But, as I said the other day in the House, when we ourselves are in difficulties today to raise funds, it will be well nigh impossible for any housing board, and that too, a Central one which has neither anything to do with the Government here nor anything to do with the State Governments, to raise any funds.

So, my suggestion is this, and I am taking it up both with the Planning Minister and with the Finance Minister, that if the LIC is agreeable to

the diversion of Rs. 10 crores further for the construction of houses under our housing programme,—it may be for industrial housing, of which I have talked so much—and if I can get that money, then I shall get another Rs. 10 crores; that will make a total of an additional Rs. 14 crores.

Another thing that we are finding now is this, and that is very unfortunate, namely that while we are making honest efforts and very sincere efforts to find funds to implement our housing programme, some of the State Governments are even diverting the Third Plan allocation for housing to other projects. I should not say anything against any State; Madras is a very enlightened State, but Madras is one of the States which has now passed an order that no more housing should be taken up and only the residuary problem should be implemented, and whatever allocation under housing is there in the Third Five Year Plan should be diverted to some other important project. In Bombay also, there has been a severe cut.

So, I am taking up this matter too with my colleagues. The Housing Ministers of all the States are of one view and one mind, namely that no diversion should take place. I am hoping that even if this diversion from housing projects to other projects is checked, it will be able to give a certain amount of fillip to the housing programme. I have just mentioned that I propose to take up all these matters with the Planning Minister and the Finance Minister. In fact, I am not going to see them alone, but the Housing Ministers of most of the States who could come—and we decided it so in Bombay—are going to meet these two Ministers, the one who plans and the other who gives the money, on the 15th and 16th of this very month, and impress upon them the importance of the continuance of the housing programme and even of stepping it up. Beyond that, today, I am not in a position to say much.

Now, I shall come to two other schemes which are part and parcel of the housing programme. One is the *jhuggi-jhompri* scheme and the other is the slum clearance scheme. Some Members have unfortunately taken it upon themselves that even where we do something good, they either impute motives to us or belittle the effort.

A census was taken in June-July, 1960, according to which the number of squatters then was round about 40,000. It was then decided that each squatter would be given a plot of land of about 80 square yards and that would be on an ownership basis. The result was that within less than a year or eighteen months, another 20,000 squatters came and squatted on the lands, and the number went up to 60,000. My hon. friend Shri Bagri is not here at the moment. But he has got the view to which I can never subscribe that let any man come here from anywhere, squat anywhere, and according to my hon. friend Shri Balmiki, he should be regularised there at that very place; for, in that way, this problem will go on indefinitely. My own feeling is that if we keep that aspect of the matter before us and even indirectly subscribe to it, we shall never be able to do anything in Delhi at all, and all our developmental programmes, and all the progress of our construction programmes will come to an end.

So, what we have done is this. We have formulated a scheme, and under that scheme, everyone who squatted before June-July, 1960 shall be entitled to alternative accommodation when he is shifted from the place where he is sitting today. The question whether he is a Harijan or non-Harijan does not arise. The only exception that I have made is in the case of Government servants. If a Government servant is squatting, then he is the first charge on me, and under our general pool, he can be allotted accommodation. But I cannot allow a Government servant to go and squat, take house rent from me, and tomorrow claim land and then

[Shri Mehr Chand Khanna]

ask this *sisila* to go on with the Government of India. As you know, the number of Government servants in Delhi runs into thousands and thousands.

The other exception is in respect of an employees of the NDMC. Those employees of the NDMC, who may be displaced on account of the construction of flats for Members of Parliament on Rafi Marg, if they are entitled, must be provided with alternative accommodation, and we are going to do that. But the responsibility will be that of the local body concerned. If the local body concerned is not in a position to build, we can consider giving them some loans. But, apart from that, leaving out the Government servants who are the responsibility of the Government of India and the employees of the local bodies who are the responsibility of the local bodies concerned, every squatter who is there and who has squatted there before June-July, 1960 will be provided with alternative accommodation; if his name has been left out by mistake, I am even prepared to give him the benefit of an enquiry being made, and if he can prove that he was there before June-July, 1960, he shall be counted, he shall be enumerated, and he shall be provided with alternative accommodation like any other squatter, whose number runs to nearly 50,000 to 60,000.

**Shri Indrajit Gupta** (Calcutta South West): What kind of proof will be required? What sort of proof will he have to furnish?

**Shri U. M. Trivedi** (Mandsaur): The satisfaction of the Minister.

**Shri Mehr Chand Khanna:** No. First of all, the proof may be his name in the electoral roll, if his name is there; then, if his son is going to school, the father's name will be there, and his address will be there, and he may be receiving certain letters at that address. If there is any proof which will even be acceptable to my hon. friend Shri Indrajit Gupta who seldom sees eye to eye with me, I am prepared to accept it. My intention is this. If I am prepared to take 60,000 persons, a few hundreds here or there will not make any difference. To that extent, I am not going to belittle either the scheme or the effort. If any reasonable proof, any circumstantial evidence, can be produced to show that the man did squat there before June-July 1960, it shall be the responsibility of the Government of India to provide alternate accommodation. I boldly make that statement. But in making that statement, I want consideration, help and co-operation from my hon. friends opposite. I shall take charge of the squatters. I shall set up all these camping sites for them. My programme is to set up about 40,000 camping sites during one year, take them there and then gradually start developing sites. When I take them there, I will try and make provision for electricity or light, water; we will give them schools, we will give them reasonable facilities—even of hospital. But I want co-operation from my hon. friends opposite. If you are in agreement with my scheme, please extend to me your hand of co-operation. If you think there is something wrong or faulty with my scheme, I am prepared to sit around with anyone of you and discuss in various aspects of the scheme. The moment you tell a man that he can become owner of a piece of land in Delhi by unauthorised squatting—if we accept that principle—that will be the end of any regular development anywhere in Delhi or in any other part of India.

Another thing. I have said so—I am only repeating myself—that with a view to implement this *jhuggi-jhopri* scheme, and we want to go at a very fast pace, some things have to be done. Our difficulties are.....

**श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : जब सरकार उन से टैक्स ले रही है और वह टैक्स लेने में सरकार अन-अथाराइज्ड नहीं है, तो वह

कंस्ट्रक्शन कैसे अनअथाराइज्ड हो सकता है ?

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं इस बात का जवाब देकर दूसरी तरफ चला जाऊंगा । झुग्गी झोंपड़ी वाले मेरे भाई दिल्ली में रहते हैं । वे मेरे वोटर हैं । मैंने हर एक झुग्गी झोंपड़ी जाकर देखी है । वे लोग रहते भी मुफ्त हैं, उनकी बिजली और पानी भी मुफ्त है और उनके स्कूल भी मुफ्त हैं । वे तो मुफ्त रह रहे हैं । अगर जलती है, तो मिट्टी की झुग्गी जल जाती है । किसी का मकान नहीं जलता है । लेकिन उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है । कोई टैक्स नहीं देता है । माननीय सदस्य तो मुजफ्फरनगर में रहते हैं...

**श्री यशपाल सिंह** : मेरा मतलब डीमालिशन स्कीम से है । उनके मकान गिराये जा रहे हैं ।

**श्री भक्त दर्शन** (गढ़वाल) : माननीय सदस्य सहारनपुर के हैं ।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : सहारनपुर के हैं ?

**श्री यशपाल सिंह** : मंत्री महोदय सही फरमा रहे हैं । मैं मुजफ्फरनगर से ही हूं ।

उनके मकानात गिराये जा रहे हैं । लेकिन जब सरकार उन से टैक्स लेती है, तो वे अन-अथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन कैसे हो गये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : माननीय सदस्य मुझे माफ करें, मैं नहीं जानता कि टैक्स के उनके माने क्या हैं । अगर माननीय सदस्य श्री मोरारजी देसाई के टैक्स की बात कह रहे हैं, तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेहरचन्द खन्ना का उन पर कोई टैक्स नहीं है । वे मुफ्त रहते हैं । हमारी मिनिस्ट्री का उन पर कोई टैक्स नहीं है । लेकिन उनके साथ मेरी बड़ी भारी हमदर्दी है । उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा । अगर न पकड़ते, तो मैं यहां भी न होता और शायद माननीय सदस्य की तरह... । मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

**श्री यशपाल सिंह** : सरकार की ज्वायंट रेस्पांसीबिलिटी है ।

**Shri Mehr Chand Khanna:** I was going to say that the Public Premises (Eviction) Act, which was formulated a long time ago and passed by this House, has with the lapse of time been found to be inadequate; some amendments have to be made if the scheme is to be implemented. First of all, there is a time-lag of 30, 45 and 90 days. Notices are given. Then there are appeals. Then are writ applications and all that. It is a very long process. We want to cut short that process. Then we want to make re-squatting a penal offence. Suppose a man is living in a *jhuggi-jhopri*. We offer him an alternative site. He goes there. Having taken a plot of land there, as has generally happened, the man comes back and starts re-squatting. In that way, nothing will be done. What I want the House to do is to give me full facilities to proceed with it. Notices to be given—yes, appeal—yes, time factor—yes, alternative site—yes, but if after having gone there, he comes back and re-squats, that must be a penal offence. He must be prosecuted and fined, he may even go to jail. Otherwise, it is not going to stop.

I happen to be a refugee—I am proud to be one. I have dealt with this question and have received compliments and bouquets. But this development started with me. We squatted. We got allotments. Either I kept mine with myself or gave them on rent or possibly sold them and started re-squatting again. This is a *bimari* that has gone on in Delhi. We must put an end to it.

I now come to slum clearance. This scheme is applicable only to six big cities in India— Delhi, Kanpur, Bombay, Madras, Ahmedabad.....

**The Deputy Minister in the Ministry of Economic and Defence Co-ordination (Shri Jaganatha Rao):** Calcutta and Hyderabad.

**Shri Mehr Chand Khanna:** My old colleague has come to my rescue. The names are: Calcutta, Bombay, Madras, Ahmedabad, Kanpur and Delhi.

So far we have spent about Rs. 26 crores on the scheme and built about 82,000 houses. They have been sanctioned; they may be in the process of construction. I have not got the exact figures. It is a very essential scheme. It is a good scheme. We do not want to see the slums. Whether my house is big enough to have a race course or it is big enough to have a polo ground, this is neither here nor there. What is important is that those unfortunate people who happen to be Indians, who have the same right as I have as a Minister, should also have a shelter. But the implementation of the slum clearance scheme even under the Slum Clearance Act has presented very great difficulties—about valuation of the land, fixation of rent, the man being taken away from the slum area again coming back etc. Then some of these schemes have to be implemented through the landlords. The landlords, as is well known, in many cases are not very sympathetic, because the slum dweller will not pay them the regular market rent. Land values have gone up. If we take the normal, market value of the land into account, and the construction cost, no slum dweller can be taken back and kept there.

In this connection too, I am bringing forward a Bill arming Government with certain powers. I do not want the landlord to suffer. But I want him not to behave in a way that he goes and asks him to pay the economic rent which is entirely beyond his paying capacity.

Having dealt with these social schemes, I want to come to the construction programme of the PWD. Mahy bouquets were given to this great department; brickbats were also hurled and many accusations were made. Let me confess before the House that when I came to this Ministry about a year ago, I also had certain bias, prejudices and inhibitions against this department. To be fair, I thought I should look into the question at a very close quarter. I met the officers of the department, I met the architects, I met the artists, I also met the contractors, town planners and so on and so forth. After having had a frank talk, personal as well as in conferences, with them and having also had two or three meetings with the contractors, I found that the procedure for the sanction of the schemes, the procedure for the award of contracts and the power that flows from the Ministry to the Chief Engineer and from the Chief Engineer to the officers on the spot is so inadequate that if all that is to be accepted and followed, we will never be in a position to undertake any programme. I do not say there is no corruption, but I do certainly hold and maintain that with the co-operation that I am getting from my staff, I personally feel that we shall be able to deliver the goods, that with the fellowship that I am trying to create between the officers of the public works and the Ministry there should not be the same cause for complaint as up till now.

I want to add one thing more. The other day a question was asked in the House, and I think the Home Minister or the Minister of State, Shri Hajarnavis, replied to it. The question was about raising the age limit of retirement from 55 to 58, why a man, once he is given extension, cannot automatically go up to 58. I fully agree that if at the age of 66 I can be made Minister, there should be no difficulty for a Government servant to go on up to 58, but one thing I am going to do in the Public Works Department, and I have said so. If I find the record of an officer not good,—I may forgive inefficiency, but I shall never forgive lack of integrity and corruption—if I find there is an officer in my Ministry,

in the Public Works Department, who has doubtful integrity, he is not going to get any extensson from me. If any action has to be taken, action shall be taken. But my idea is not to start a witch hunt. That is not my intention at all. Any officer who has got a good record shall have the full support of the Ministry. In other cases, there is no way out of it.

So, I have been trying to create a fellowship among the contractors, the engineers and the Ministry, and we have taken certain remedial measures too to see that our construction programme is stepped up. I will only mention them briefly. I have no intention of taking much time of the House.

We have reorganised the department. I will take a minute or two to explain what I mean by reorganisation. Previously, all my Additional Chief Engineers had their headquarters in Delhi. A man may have his work in Madras or Bombay or Calcutta, but he had his headquarters in Delhi. Similarly, the officers in charge of electricity had their headquarters in Delhi. Delhi has got a great charm as you know perfectly well. Whether he is an M.P., a Minister or a *juggi-jhompdiwala*, nobody wishes to leave Delhi once he comes to Delhi. Today we have decentralised the department. I am posting one Additional Chief Engineer in Calcutta. I have already done it. I am posting another to Bombay. This process is going on, so that there is direct supervision. The man is on the spot, we will even save money. All this unnecessary touring and the contractors coming to Delhi all the time will be eliminated. At the same time, when they know that the Additional Chief Engineer is on the spot, it is bound to have a certain salutary effect.

Similarly, procedure for the sanction of works has been simplified as I have just said, and large powers have been delegated. Rules regarding security deposit have also been relaxed and liberalised. Shri Mohan Swarup referred to that. Previously, the security deposits were not being repaid in time and naturally if a contractor is to keep his money locked up, the Government pays for it, he does not pay for it. I seldom come across a contractor who has paid anything from his own pocket. It is the Government that suffers. So, we have simplified that. We have also simplified our contract form, and we have appointed an additional arbitrator to look into the cases of arbitration, so that these cases can be disposed of as quickly as possible.

I now come to the direct construction programme undertaken by this Ministry. We have launched upon a big and massive construction programme. That programme, which is the direct responsibility of the Ministry, can be divided into two heads: office accommodation and residential accommodation. I shall first deal with office accommodation.

Delhi was built a long time ago. It has been expanding. I do not want to talk of the first war, but during the second war a large number of hutments and temporary shelters were put up. They are still there. The emergency has caused a very heavy strain upon us. We want big office accommodation for obvious reasons, for defence and all that. What we have done temporarily is to use these exhibition pavilions and grounds for our offices. The money that we have spent possibly will be repaid within one month, if one were to calculate the rent at which this accommodation is being hired.

We are very short of office accommodation. We have 21 lakh sq. ft. in old hutments; we had taken six to seven lakh sq. ft on lease and requisition as far back as 1940, 20 years ago, and we are paying rent for that. Even the Supreme Court has held and given a ruling against us that such requisition can no longer hold good. That was before the emergency started. Similarly, we hired accommodation, and now the rates are—it might shock

[Shri Mehr Chand Khanna]

the House—one rupee per square foot per mensem, that is on concession. It means if you have a room of 10 x 10 in Delhi and the Government wants to hire it, Government has to pay a rent of Rs. 100 per mensem. The figure is even going up to Rs. 1-8-0 per square foot.

So, we are now undertaking a big construction programme to fill up the gap in office accommodation of all these years. We want roughly about 34 to 35 lakh sq. ft. of office accommodation. My submission for the consideration of the House is that if I build a house or an office, it costs roughly Rs. 22 to Rs. 24 per square foot. If I take the usable area, leaving out the corridors, bath rooms and the veranda, it comes to about Rs. 45. So, with three to four years of the rental that we have to pay, we can put up a building. It is not magnificent buildings, as was stated day before yesterday. If I go to the market hiring property at exorbitant rates, that does not solve my difficulties. that does not add a single house or a single square foot of accommodation to the Government. But if I build another house, or an office, then I am adding on to the accommodation. The same thing applies to the Government servants.

We give them a house rent allowance. I know what their difficulties are. I know the difficulties of the sixty to seventy thousand Government servants in Delhi who have to hire accommodation. The rents in Delhi are fully known. They are very exorbitant. If a Government servant takes a house from me,—and their number is only 30 to 35 per cent —he has a certain sense of security that he has got a house. But we know what the difficulties are of the Government servant who does not have a house and has hired one from outside. So, what we are doing is this. I have sanctioned this year a big programme to the extent of Rs. 15 crores. I am not casting any aspersion on anybody. Far be it from me. But during the last five years, the period previous to 1962-63, the total construction programme sanctioned by this Ministry is only Rs. 7:5 crores, less than half of the programme that we have sanctioned this year. We have been acquiring houses or hiring them. In the interest of all concerned. it will be good if we have a massive construction programme. We are not putting up any luxury buildings, as was stated that day. These buildings should stand the test of time. If we are going to spend Rs. 40:45 per square foot on a multistorey building, we have to see that they answer certain specifications; we cannot and must not waive those specifications. Previously, we undertook only single storeyed constructions. It is said that the bungalows of Ministers are very spacious: there are a large number of servants' quarters and so on. That is not my fault; we never built them; the Britishers built them.

**Shri Indrajit Gupta:** But why do not two Ministers share a bungalow?

**Shri Mehr Chand Khanna:** I am coming to that. I was saying that we were going to have multi-storey buildings. Instead of building one house over two acres of land, we are now going to build at least twenty flats in eight storeys over that place so that there can be maximum and intensive utilisation of land in accordance with the master plan. A little while ago, I said that 60,000 Government servants are without houses. Very rightly Shri Gupta asked: why don't you share accommodation? It is a good thing. Who is to set the example? (*Interruptions.*)

**Shri Indrajit Gupta:** Ministers.

**Dr. L. M. Singhvi** (Jodhpur): It will create problems of co-ordination.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I have to give a reply to Dr. Singhvi; I wish you had not anticipated or precipitated this question. I will not indulge in that at very great length. There are Government servants who are living

here: they are in very great difficulty; they come to me every day. We have completed about 4,000 houses this year; we have about 5000 houses under construction. That number is small compared to the present demand of 60,000 houses. About office accommodation, 35 lakhs square feet are needed. I should be able to complete my programme within the next three or four years. Already we have sanctioned to the extent of 25 lakhs square feet; 9 lakhs square feet are under construction. But in the case of residential housing for Government servants I am sorry that I am not in a position to give the same amount of satisfaction for obvious reasons. First of all, land has to be acquired and then developed. Then, even if we construct 6000-8000 houses a year, it is a very big programme by itself, there is the problem of water, electricity and the civic amenities such as schools, hospitals, buses, etc. All these things have to be taken into consideration. It is no use putting up a house with brick and mortar and take a friend of mine who works in the North Block to a house eight or ten miles away and put him there. That is not my intention at all. We will intensify our construction programme in the nearest possible area. There is a charge against us that the Ministers, MPs, members of the Planning Commission, and the Public Service Commissions and the Judges of the High Court live very near to their place of office. It is unfortunate that people are taken too far out. I accept it. There is a lot of hardship in that. That is why we are going to take up intensified construction programme and multi-storey buildings.

I was talking about Government servants. We have a shortfall of 60,000 houses. Even if I complete 8000 every year, it is going to be a long time; it may take eight years or more. Till then if a Government servant living in a hired house were to come to me and say or ask me what am I going to offer to him, I am sorry to say that I can only say one thing. What I have done is this. I have liberalised the rules of allotment; I will allow them to share accommodation with a Government servant who is entitled to it. I have told him that I shall not penalise him because he refuses any allotment. We will also see that these houses which are in the general pool are not allotted to any outsider; whether he is a retired Judge or a retired Governor, if he is going to get any honorary job in Delhi and house is part of that job, the Ministry concerned shall have to find the house for him; he will not be a charge on the general pool. The idea is to conserve houses for the general pool. One of the newspapers remarked about this: grace and favour allotment. I have stopped that; there is no grace and favour allotment. We have avoided the system of priorities. Till now people did not have any inkling or idea as to when their turns were going to come. That creates a lot of difficulties for me. Some of my friends and colleagues are annoyed with me but now they are beginning to appreciate this step. we did away with this priority business, it is because that means nothing else but favouritism. I am prepared to look into hard cases: I do not say that I shall not look into them. If a man is sick or in difficulties or his mother is ill—all these things can be taken into consideration. But by and large our approach today is that we shall make these allotments on the normal basis; there shall be no priorities except in the case of serious illnesses.

I will touch one or two more points. My old Minister friend, Shri A. P. Jain is not here. He made scathing criticism about the sale of lands in Delhi and said that we were profiteering and wondered whether the Defence of India Rules could be applied against us.

**An Hon. Member:** Against Ministers.

**Shri Mehr Chand Khanna:** In a way he is correct because the land prices

[Shri Mehr Chand Khanna[

in Delhi have gone up very high. But Delhi is no exception; it is happening all over the country. I was in Bombay about a month ago and I wanted some lands for the construction of houses for Government servants. I saw the Finance Minister of Bombay, Shri Barve, an old friend of mine who was to a great extent responsible for the setting up of the township of Faridabad: he was then our Administrator and I do not think many people know this in this House. I asked him: can you give me this land? I think it was called Cuffe Parade. It was somewhere near the Oval, near Churchgate extension. The price was Rs. 1100 a square yard, he said. Why don't you allot that? I asked. He said: to save my neck from the charge of favouritism, being charged tomorrow that I have given this valuable land through the back door to A, B, C, or D. That is the policy that I have adopted in Delhi. I know land prices are high. But if I were to allot this land to anybody for Rs 200 or Rs. 300 per sq. yard, tomorrow there shall be a charge against me. I do not want to be named; I hope my name never comes up as it has come up in the House in certain other matters. Either it should be favouritism or it should be put through the public market. I put it up in the market, under the hammer. There is nothing wrong about it. Is it justified that in this poor country at the expense of the tax-payer we should subsidise housing for the richer class or the middle class or the class to which Shri A. P. Jain belongs..... *(Interruptions.)*

**Dr. L. M. Singhvi:** For the sake of old friendship.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I believe in new friendship and I am coming to you presently. That is our approach. I am not responsible for freezing these 50,000 acres of land. I am not responsible for making certain co-operative societies eligible and certain co-operative societies non-eligible. I am not responsible for the implementation of the master plan or its formulation. The land has been frozen by the Chief Commissioner of Delhi. If it is asked of me whether it is right, I shall certainly say "Yes; you did the correct thing." That land is being developed by him and it shall be sold. I do not know what the procedure is, because the Minister in charge is the Home Minister. It, however, does create a certain amount of confusion as Shri Shiv Charan Gupta said the day before yesterday. I am the Minister of Works and I am also the Minister of Housing. I have to undertake the construction programme; the nazul lands are under me and the Government lands are under me. But if any land is acquired for development, that is done by the Chief Commissioner under the Ministry of Home Affairs. I have nothing to do with it. So, I do not plead guilty about it.

**14 hrs.**

The same is the case with the master plan. Historically, they may be all right,—the implementation of the master plan or the DDA being with the Ministry of Health. But functionally, from the functional point of view, I feel that they should come to my Ministry. I am not asking Dr. Sushila Nayar to give them to me, because I have already had brickbats and bouquets and now, in my old age and with bald head, I am not going to expose it further! That is not my idea at all. But what I am placing before the House is this: you take water, for instance. The other day, some hon. Members were getting very much agitated about water which has not reached the MPs' quarters. But that is dealt with by another Minister—the Minister of Irrigation and Power. Electricity is dealt with by the Minister of Irrigation and Power.

**Dr. L. M. Singhvi:** That is the difficulty with this Government The responsibility is shoved on to the others.

**Shri Mehr Chand Khanna:** What I am trying to say is this. With the growth of Delhi, there are problems coming up, problems which were not

visualised, such as the growth of population, the way it is growing.....

**Shri Sham Lal Saraf** (Jammu and Kashmir): The responsibility must be owned.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I am not disowning responsibility. My hon. friend was himself a Minister in Jammu and Kashmir and he knows what the responsibilities are. What I was saying is this. I do believe that this diversified control is not conducive to the best development of the capital. I accept that. I also feel that there should be a unified control. I also agree that there should be an agency which should deal with all these matters. I am not in a position to answer what I am going to do.

**Dr. L. M. Singhvi:** It is a very candid confession.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I can assure the House about one thing. I will bring all these matters to the notice of the Home Minister. I wish his Demands had come later than mine so that the hon. Member could put these questions to him. But I wish to assure the House and you, Sir, that I shall take up this matter with the Home Minister. I earnestly feel that it is in the interests of the capital; the development scheme the *juggi-jompri* scheme, or the slum clearance scheme—there are autonomous bodies, and there are so many Ministries functioning. Taking that into consideration, I feel that we should do something in this connection.

I would not take much time, but I shall now turn to Dr. L. M. Singhvi's remarks.

**An Hon. Member:** New front!

**Shri Mehr Chand Khanna:** No. He talked about MPs' accommodation. I am glad that you are in the Chair, Sir. No allotments are made by the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation in this regard. There is an allotment committee of the Rajya Sabha, and there is a sub-committee on accommodation—I do not know, and I heard of it for the first time today. But we do not make any allotment. Whether it is a flat or a bungalow, again it is done by the House Committee of both the Houses. The other day, objection was taken to the allotment of houses to a certain set of MPs—whatever name you call them, it is no concern of mine. But it was a terminology or a phrase which has come down to me from my predecessors and so I used it inadvertently the other day. Now, if some MPs are no longer MPs and if they have not vacated the houses occupied by them, I am taking necessary action to evict them, but I shall tell you that this Public Premises (Eviction) Act is a very dilatory thing. Then, again, pressures are also brought to bear on us by A, B, C.....

**Dr. L. M. Singhvi:** Reference was made to a special set of MPs—the distinguished MPs!

**Shri Mehr Chand Khanna:** I am not going to use the work "distinguished". I got a rap on the knuckle the other day! There are about a dozen houses which are placed at the disposal of the Minister of Parliamentary Affairs and he makes those allotments. I do not make those allotments.

**Shri Indrajit Gupta:** So, the cat is out of the bag.

**Shri Mehr Chand Khanna:** My job is only to evict. My job is not to allot.

**Dr. L. M. Singhvi:** That is what I was eliciting.

**Shri Mehr Chand Khanna:** If the food is bad in the hostel, the responsibility is mine. But if the caterer is to be appointed, then the Rajya Sabha House Committee or the Lok Sabha House Committee has to be consulted and their wishes taken into consideration.

श्री त्यागी (देहरादून) : इसके मानी यह हैं कि आप उजाड़ने वाले मिनिस्टर हैं बसाने वाले नहीं हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यह मेरी बदकिस्मती है। जब रिहैबिलिटेशन में था, तो बसाने वाला था, लोगों को मकान देता था। अब जब इस मिनिस्ट्री में आया हूं, तो चाहे मिनिस्टर हो या सरकारी मुलाजिम, हर एक को निकालना और उजाड़ना मेरा काम है, इसको मानता हूं, तसलीम करता हूं।

Now, a pertinent remark was made by Dr. L. M. Singhvi. I feel that it needs an answer. The remark was about the accommodation that is allotted to Members of Parliament. I cannot divest myself of the responsibility as a Housing Minister, to provide accommodation to MPs and all those who are a charge on me. We have three or four types of houses here. There are about a dozen houses which are a class by themselves. Then there are about 160 or 170 or 180—I forget the number—houses on the Rajendra Prasad Road and Maulana Azad Road; they are old bungalows. Then there are the flats which were built on the North Avenue and South Avenue long before I took charge of this Ministry. When I examined the problem of shortage of accomodation in Delhi, I also applied my mind to the accommodation that is needed for MPs. I honestly believe and feel that if an MP is to discharge his duties, like any other Minister or any other person he has to be provided with adequate accommodation and it should be as near to Parliament as possible. If he lives in Vinay Marg or far away, it is going to cause discomfort and irritation, and the only person of whom he can think of and talk about is possibly the Minister. It is quite right. So, I looked into this matter and we found that we were short of about 150, 160 or 170 quarters. Presently, we have started the construction of flats near the Willingdon Hospital, in the North Avenue; they are under construction, and we have sactioned about 150 flats to be built on Rafi Marg. We have also sanctioned a new club for MPs It will be a good club. I am hoping. As I said, Members of Parliament should be provided with adequate accommodation. But personally I feel that if an MP is given a free house, it would be much better.

**Shri U. M. Trivedi:** That is what we want

**Shri Mehr Chand Khanna:** That will solve all my difficulties as Minister of Works, Housing and Rehabilitation. Let me tell you why I have made that suggestion. I have thought about it. Under the rule, an MP is to get a house, the maximum rent of which is not to be beyond Rs. 105. That is the rule, It is entirely a different thing: if he stays for 12 months he gets a 25 per cent subsidy. In the assessment of rent, we do not take the value of the land into consideration. We do not take developmental charges into consideration. We only take restricted departmental charges. In other words, we take only brick and mortar into consideration, and having done that, we assess the rent up to a certain percentage.

**Shri U. M. Trivedi:** After depreciation has gone to zero.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I am saying exactly what you want me to say. That is the position. Taking Rs. 105 as the basis, you find that there are a number of houses the rents of which are more than Rs. 105. We scale it down to Rs. 105. Then again, when we give a concession of 25 per cent, we bring it down to Rs. 70 or Rs. 75. Then, let us take it that some additions and alterations are made to the house, say, the house occupied by Shri Tyagi. He will not misunderstand me. Supposing tomorrow he goes out and he is not returned by his constituency.

That house will be again allotted to some other M.P. Then the rent will again be reduced to Rs. 105. With the execution of the additions and alterations, the rent goes up to Rs. 115, but when that M.P. leaves it, the rent again goes down to Rs. 105. We cannot charge more than Rs. 105.

That being the position, I have to consider the construction programme or the space which is required for the M.P. for his legitimate needs. If he has to live for 6 months in a year in Delhi, he must naturally have his family here. For Mr. Tyagi it is all right; he is in an unfortunate position. But others naturaly want their families. If there is going to be a direct relation between the rent and the construction cost, I am sorry to say that we will not be able to do any thing beyond that. I would submit to you, Mr. Deputy-Speaker and through you to the hon. Speaker for his consideration, let this question be examined as to what should be the normal accommodation required for the M.Ps. That shou'd be decided and laid down. After all, the Parliament is a sovereign body and if it takes a decision, as Minister for Works, Housing and Rehabilitation, I have to see that the decision is implemented.

**Shri Daji** (Indore): 50 per cent of the accommodation is taken up by the Ministers.

**Shri Mehr Chand Khanna:** He is far wrong. Out of 750 the accommodation taken by the Minister is only 48 or 49.

**Shri Daji:** Not the total, but each individual case.

**Shri Mehr Chand Khanna:** There again Mr. Daji is quite wrong, because having worked for 11 months in a year in this Ministry, I know every inch of land; I know every file and I have gone through it. So, don't take up the question of M.Ps. and Ministers.

**Shri Daji:** Why not?

**Shri Mehr Chand Khanna:** My question is, whether he is an M.P. or a Minister, if a Minister is entitled to a free house, give a free house to the M.P. Or, lay down that this should be the accommodation which should be provided to an M.P. Lay down some yardstick. That accomodation being there, I should be told to build houses according to that specifiation. Let the Speaker take it up. Let the Chairmen of the House Committees of the two Houses be there. Let the leaders of the opposition groups be there. The Finance Minister should be invited and I should be also invited. Let us decide this question once and for all as to what accommodation should be considered adequate for the reasonable needs for an M.P. who has to spend a large part of his time in Delhi. I may tell Dr. Singhvi that I am fully in sympathy with the idea he put forward day before yesterday; I have nothing to say against it. If we can live in big bugalows, certainly Members of Parliament are also entitled to some kind of reasonable and adequate accomodation.

**Shri Inder J. Malhotra** (Jammu and Kashmir): But not free water and electricity; otherwise the same trouble will arise.

**Shri Mehr Chand Khanna:** The hon. Member is quite right. Whether you impose a ceiling upon yourself or whether you have free electricity and water, whether you have a free house like Ministers and have other amenities, it is a matter for the House to decide. I am not deciding that, because I have not even got the power to allot a House to any M.P. and I said so in the beginning.

**Dr. L. M. Singhvi:** Can you not add a few more larger houses to the pool for M.Ps.? This has also been the recommendation of the Housing Committee to the Government?

**Shri Kapur Singh** (Ludhina): The propriety of a matter is one thing and the legality is another thing. He is confusing the two.

**Shri Mehr Chand Khanna:** As I said, my attitude is very helpful, practical and forthright. My idea has been to help and serve my M.P. colleagues, because you are my Parliament; you are my sovereign body and if I have to remain and work, I can remain and work only with your willing cooperation. I want that cooperation and I do not want to do anything which is not considered right or proper.

A suggestion has been made by Dr. Singhvi and there is a lot of force in that. That will be a matter again for the Speaker and others to consider. If some more houses are to be added to the M.Ps.' pool it will naturally impinge upon the houses that we allot to the Government servants. Then, what would be the terms of allotment of those houses? I can understand this decision being taken, namely, to give 10 or 15 more houses to them, like to anybody else, under F.R. 45A. These matters may be considered. I can consider that. In all these matters, if any reasonable via media can be found, my M.P. colleagues shall not find me wanting in that direction.

I am sorry I have taken up so much time....

**Shri Dinen Bhattacharya** (Serampore): You have been dealing only with Delhi.

**Shri Mehr Chand Khanna:** As far as rehabilitation is concerned, the Deputy Minister dwelt upon it day before yesterday. I have nothing to add. He made certain categorical statements. One statement is that Dandakaranya scheme is being implemented and shall be implemented. The priority of Dandakaranya scheme is that of the displaced persons from East Pakistan who were in camps in West Bengal. They should go there. Thirdly, as regards the 10 per cent quota, we are not against it. There is the vacuum of 5000 families in Dandakaranya; whether 10 per cent go there from non-campers or from campers, is a matter of mutual adjustment. To that we have no objection whatsoever.

Then there is the refugee problem in West Bengal. That is being tackled. We are making allocations and funds. I do not know what is the difficulty. If Mr. Guha were here, I would have told him that I got the impression from his speech that he was speaking possibly in 1953 and not in 1963. We have spent Rs. 400 crores on the rehabilitation of displaced persons out of which over Rs. 200 crores have been spent on the rehabilitation of displaced persons from East Pakistan. We have spent Rs. 15 crores on the Dandakaranya scheme so far. Our budget for Dandakaranya is Rs. 4 crores next year.

**Shri N. R. Ghosh** (Jalpaiguri): Sealdah station is as dismal as before.

**Shri Mehr Chand Khanna:** Sealdah station shall remain a chronic problem. It has come up here many times. Sealdah station can only be cleared if an assurance is given by a certain section in this House that they shall not resort to squatting again. I have cleared it once, twice, but so long as Sealdah station remains a political problem, it can never be cleared. That is my feeling. If you say Sealdah station is bad, am I responsible for it? What is the number of non-displaced persons today at the Sealdah station? Let it be cleared once and for all. When we have spent Rs. 200 crores, a few lakhs is not much, but that is not the point.

**Shri Y. S. Chaudhary** (Mahendragarh): But who is responsible?

**Shri Mehr Chand Khanna:** I am not responsible for that. That is the only positive statement I can make

I have taken so much time. I am very grateful to all the hon. Members for the patient hearing they have given.

**Dr. Ranen Sen** (Calcutta East): That day I had raised the question of rentals of the industrial housing scheme as well as of the houses built under the Slum Improvement Act. The rents are too high. Is it within the power of the Central Government to do anything in this regard?

**Shri Mehr Chand Khanna:** Under the existing pattern, there is a certain amount of grant and subsidy laid down. We are sticking to that. We have no intention at the moment of liberalising it. But I intend doing one thing more. A demand has been made by some of the slum dwellers and industrial workers that these houses may be sold to them on a hire-purchase basis through easy instalments. I am following that proposal. If that can be done, with the money that I would make, I can plough it back for the construction of more houses

**Dr. L. M. Singhvi:** I would like to know whether the Government is inclined to frame a comprehensive national plan for slum clearance. We are told that the Government of India at the moment is responsible for only six slum clearance programmes. In view of the fact that the Prime Minister and many important people in the country have said repeatedly time and again that the State Government and local authorities are incapable of solving this problem, would the Minister tell us whether a more massive programme is likely to be undertaken in the foreseeable future?

**Shri Mehr Chand Khanna:** An enquiry committee was set up under the chairmanship of my colleague, Shri A. K. Sen, which looked into this question. They submitted a report, which was accepted. The approach was that we will take six big towns in India today. But it was left to the State Governments; if they want to extend the scheme beyond these six to some other towns in their States, they can do so. But, as I said in the beginning, firstly, the difficulty is about the law. That we are going to amend. Secondly, if I can get some more money—and for that I want the co-operation and the help of the hon. Members here—I may be able to achieve better results.

**Shri Balmiki** *rose—*

**Mr. Deputy-Speaker:** Ordere, order. I shall now put all the cut motions together to the vote of the House.

*The cut motions were put and negatived.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necesasry to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 101, 102, 103, 104, 105, 144, 145 and 146 relating to the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation."

*The motion was adopted.*

[*The motions for Demands for Grants which were adopted by Lok Sabha are reproduced below—Ed.*]

DEMAND NO. 101—MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND REHABILITATION

"That a sum not exceeding Rs. 82,12,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964 in respect of 'Ministry of Works, Housing and Hehabilitation' "

DEMAND NO. 102—PUBLIC WORKS

"That a sum not exceeding Rs. 31,62,96,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Public Works'."

DEMAND NO. 103—STATIONERY AND PRINTING

"That a sum not exceeding Rs. 8,93,02,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Stationery and Printing'."

DEMAND NO. 104—EXPENDITURE ON DISPLACED PERSONS

"That a sum not exceeding Rs. 7,69,85,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Expenditure on displaced persons'."

DEMAND NO. 105—OTHER REVENUE EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND REHABILITATION

"That a sum not exceeding Rs. 71,08,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Other revenue expenditure of the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation.'"

DEMAND NO. 144—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS

"That a sum not exceeding Rs. 7,27,83,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Capital Outlay on Public Works'."

DEMAND NO. 145—DELHI CAPITAL OUTLAY

"That a sum not exceeding Rs. 7,22,33,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964 in respect of 'Delhi Capital Outlay'."

DEMAND NO. 146—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND REHABILITATION

"That a sum not exceeding Rs. 8,32,60,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Other capital outlay of the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation'."

MINISTRY OF LAW

**Mr. Deputy-Speaker:** The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 75 to 77 relating to the Ministry of Law for which 3 hours have been allotted.

DEMAND NO. 75—MINISTRY OF LAW

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 37,25,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of 'Ministry of Law'."

DEMAND NO. 76—ELECTIONS

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 1,27,59,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1964, in respect of Election'."